माननीय न्यायालय रामेश्वर सिंह मलिक, जे.

साहब सिंह @ साभी-याचिकाकर्ता

बनाम

धरमवीर-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी नं. 2014 का 4649

मार्च 24,2015

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 311-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989- समन सामग्री गवाह की शक्ति या किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की जांच-धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए किया जाएगा-विवेकाधीन शक्ति का उपयोग न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयम से किया जाएगा-धारा 311 का उपयोग पक्षकारों द्वारा मामले में कमियों को भरने के लिए नहीं किया जाएगा-माना जाता है, वह याचिका पूरी तरह से गलत धारणा है, योग्यता से रहित है और बिना किसी सार के, यह विफल होना चाहिए-हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया-याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि इस न्यायालय का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि वर्तमान याचिका पूरी तरह से गलत धारणा वाली है, योग्यता से रहित है और इसमें कोई सार नहीं है, इसलिए इसे विफल होना चाहिए। हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

(para 15)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिणामस्वरूप, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाता है, हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

(Para 16)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बी. एस. ढिल्लन।

प्रत्यर्थी के वकील अरुण लूथरा।

रामेश्वर सिंह मलिक, जे.

(1) वर्तमान याचिका दिनांक 16.01.2014 (अनुलग्नक-1) के विद्वत विशेष न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') के तहत शिकायतकर्ता की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

(2) नोटिस जारी किया गया था।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'एससीएसटी अधिनियम') के तहत कुरुक्षेत्र के विद्वान विशेष

न्यायाधीश ने विवादित आदेश पारित करते हुए एक गलत दृष्टिकोण अपनाया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि यह एससीएसटी अधिनियम के तहत शिकायत का मामला था और जब अभियोजन साक्ष्य चल रहा था, तो आवेदन (अनुलग्नक पी-2) धारा 311 Cr.P.C. के तहत स्थानांतरित किया गया था, ताकि तीन और गवाहों को बुलाने और उनकी जांच करने की अनुमति मिल सके। आवेदक-याचिकाकर्ता द्वारा बुलाए जाने और उनसे पूछताछ किए जाने की मांग करने वाले तीनों गवाह मामले के उचित निर्णय के लिए बहुत आवश्यक थे। हालाँकि, विद्वत विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करके याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया। उसकी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील जगसीर सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस अदालत द्वारा पारित एक फैसले पर भरोसा करते हैं।

(4) वह विवादित आदेश को दरकिनार करके वर्तमान याचिका को अनुमति देने के लिए प्रार्थना करता है।

(5) इसके विपरीत, प्रतिवादी-अभियुक्त के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता पहले दिन से ही बहुत ही अनौपचारिक दृष्टिकोण पर आगे बढ़ रहा था। धारा 311 सी. आर. पी. सी. के तहत आवेदन के माध्यम से तलब किए जाने और पूछताछ किए जाने की मांग करने वाले गवाहों में से न तो कोई गवाहों की सूची में था, न ही यह बताया गया था कि उन्हें बुलाने और पूछताछ करने का उद्देश्य क्या था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन गूढ़ और अस्पष्ट था जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। याचिकाकर्ता कानूनी रूप से शिकायत में दी गई मनगढ़ंत कहानी में कमी को भरने का हकदार नहीं था। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश तथ्यात्मक रूप से सही और कानूनी रूप से न्यायोचित था जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए। वह वर्तमान याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करता है।

(6) पक्षकारों के विद्वत वकील को काफी विस्तार से सुनने के बाद, मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने और उठाए गए तर्कों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि ऊपर देखे गए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के हाथों हस्तक्षेप की गारंटी देने वाला कोई उपयुक्त मामला नहीं पाया गया है। ऐसा कहने के लिए, एक से अधिक कारण हैं, जिन्हें इसके बाद दर्ज किया जा रहा है।

(7) इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय के पास मुकदमे के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उससे पूछताछ करने के लिए धारा 311 सी आर पी सी के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं। तथापि, यह समान रूप से सत्य है कि धारा 311 सी. आर. पी. सी. के अधीन शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा केवल तभी किया जाना है जब यह पाया जाता है कि ऐसे किसी व्यक्ति की परीक्षा मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ति जितनी अधिक होगी, उसका अभ्यास उतना ही अधिक सावधान होना चाहिए। विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब न्याय के उद्देश्यों की मांग हो। आक्षेपित आदेश के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलेगा कि विद्वत विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय कानून की कोई त्रुटि नहीं की थी और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

(8) एक अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या धारा 311 सी आर पी सी के तहत शक्ति का उपयोग किसी भी पक्ष के अभियोजन या बचाव के मामले में बची कमी को भरने के लिए किया जाना चाहिए। इस न्यायालय को डर है कि यह धारा 311 सी आर पी सी का उद्देश्य और दायरा नहीं है। यदि धारा 311 सी आर पी सी के तहत शक्ति का प्रयोग किसी भी पक्ष के मामले में दूसरे पक्ष की कीमत और पूर्वाग्रह पर गंभीर कमी को भरने की दृष्टि से किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। धारा 311 सी आर पी सी के तहत शक्ति का इस तरह का प्रयोग इसके पीछे के विधायी इरादे के विपरीत होगा। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन अनुलग्नक पी-2 अपने आप में गुप्त और अस्पष्ट था, इसलिए इसे विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया था और इस कारण से भी विवादित आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय पर आते हुए, उसमें निर्धारित कानून के बारे में कोई विवाद नहीं है। हालांकि, इसके बारीकी से अवलोकन पर, उद्धृत निर्णय याचिकाकर्ता के लिए किसी भी मदद का नहीं पाया गया है, जो तथ्यों पर अलग-अलग है। इसके अलावा, यह कानून का तय प्रस्ताव है कि किसी भी संहिताबद्ध या न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने से पहले प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों की जांच, विचार और सराहना की जानी चाहिए। कभी-कभी, एक अतिरिक्त तथ्य या परिस्थिति का अंतर दुनिया में बदलाव ला सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पद्मसुंद्र राव और दूसरे बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य मामलों में कहा था।

(10) वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर आते हुए, याचिकाकर्ता ने अदालत के पूर्व पीठासीन अधिकारी को गवाह के रूप में पूछताछ के लिए बुलाने का भी अनुरोध किया। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रामेश्वर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस तरह के दृष्टिकोण के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। रामेश्वर दयाल मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियां, जिनका वर्तमान मामले में अनुसरण किया जा सकता है, निम्नानुसार हैंः –

रेजिना बनाम गज़र्ड (1838) के मामले में न्यायमूर्ति पैटसन द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभिलेख न्यायालय के अध्यक्ष को गवाह के रूप में परीक्षण करने की अनुमति देना एक खतरनाक उदाहरण होगा। इस संबंध में, न्यायमूर्ति पैटन ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं –
"यह एक नया मुद्दा है, लेकिन मुझे ग्रैंड जूरी को उसकी जांच करने की सलाह देनी चाहिए। वह अभिलेख न्यायालय के अध्यक्ष हैं, और इस तरह की परीक्षा की अनुमति देना खतरनाक होगा, क्योंकि इंग्लैंड के न्यायाधीशों से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उनके सामने न्यायालय में क्या हुआ था।"

यद्यपि तत्काल मामले में सत्र न्यायाधीश अभिलेख न्यायालय नहीं था, लेकिन पैटसन, जे द्वारा निर्धारित सिद्धांत उस पर समान रूप से लागू होंगे। हम एक क्षण के लिए यह सुझाव नहीं देना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय को किसी भी मामले में सत्र न्यायाधीश की परीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे उचित और उपयुक्त मामले हो सकते हैं जहां सत्र न्यायाधीश या विचारण न्यायालय की परीक्षा बहुत आवश्यक हो, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत ही दुर्लभ अवसर होना चाहिए जहां अन्य सभी उपचार समाप्त हो गए हैं। तत्काल मामले में, हम महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय के लिए सत्र न्यायाधीश का परीक्षण करने के लिए कोई अच्छा और ठोस आधार नहीं था क्योंकि मामले के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए उनका साक्ष्य आवश्यक नहीं था, विशेष रूप से जब अपीलकर्ताओं ने कभी भी सत्र न्यायाधीश के समक्ष या यहां तक कि उच्च न्यायालय में जब अपील का ज्ञापन न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, तो जीवित कारतूसों के संबंध में निर्णय में दिए गए बयानों को चुनौती नहीं दी थी।

जहाँ तक जाँच अधिकारी मुनिराज सिंह के साक्ष्य का संबंध है, वह भी आवश्यक नहीं था क्योंकि यह वास्तव में अभियोजन पक्ष को कमियों को भरने की अनुमति देने के बराबर था। भले ही हम यह मानते हैं कि उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 540 के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में उचित ठहराया गया था, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को उच्च न्यायालय द्वारा जांचे गए गवाहों के बयान का खंडन करने का अवसर नहीं देने में कानून की गंभीर त्रुटि की, जिससे अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ।

राज्य के वकील ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत अदालत अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 540 के तहत बुलाए गए गवाहों के साक्ष्य का खंडन करने का अवसर देने की आवश्यकता होती है यह तर्क, हमारी राय में, आपराधिक न्याय के मुख्य सिद्धांतों के लिए सही दृष्टिकोण की गंभीर गलत धारणा पर आधारित है। धारा 540 स्वयं प्राकृतिक न्याय के नियम को शामिल करती है। जब तक आरोपी दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि जहां अभियुक्त के विरुद्ध कोई नया साक्ष्य स्वीकार किया जाता है, वहां निर्दोष होने की धारणा कमजोर हो जाती है और अभियुक्त को पूरी निष्पक्षता से उस साक्ष्य का खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार अभियुक्त द्वारा किसी मामले के बचाव में अपरिहार्य कदमों में से एक है और उसी राशि का इनकार न केवल दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है और प्रसिद्ध कहावत ऑडी अल्टेरम पार्टेम का अपमान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 540 इस प्रकार चलती है –

"कोई भी न्यायालय, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है, या उपस्थित किसी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है, या पहले से ही जांच किए गए किसी व्यक्ति को वापस बुला सकता है और फिर से पूछताछ कर सकता है; और अदालत ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाएगी और जांच करेगी या वापस बुलाएगी और फिर से पूछताछ करेगी यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।"

पीठ ने कहा, "इस प्रावधान के सावधानीपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कानून ने अदालत को पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की सभी शक्तियों से लैस किया है और जब तक दोनों पक्षों को ठीक से नहीं सुना जाता है, तब तक पूर्ण न्याय नहीं किया जा सकता है। यदि न्याय और निष्पक्षता की भावना के बिना निर्णय लेना है तो "मामले का न्यायसंगत निर्णय" शब्द अर्थहीन और बिना किसी महत्व के हो जाएंगे।"

(11) अगला प्रश्न जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या न्यायालय को धारा 311 सी आर पी सी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी पक्ष को अपने मामले में बची कमी को भरने की अनुमति देनी चाहिए, जिसकी कीमत पर दूसरे पक्ष को गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर जोरदार 'नहीं' है और होना चाहिए, क्योंकि यह धारा 311 सी आर पी सी का उद्देश्य नहीं है। न्यायालय द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण को मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से भी समर्थन मिलता है4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मोहनलाल शामजी मामले में निर्णय के पैरा 10,18 और 27 में निर्धारित विधि के सिद्धांत जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपयुक्त रूप से लागू होते हैं, निम्नानुसार हैं:-

"साक्ष्य के कानून में यह मुख्य नियम है कि किसी तथ्य या मुद्दे के बिंदुओं को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष सबसे अच्छा उपलब्ध साक्ष्य लाया जाना चाहिए। लेकिन यह या तो अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष पर छोड़ दिया जाता है कि वह सबसे अच्छा उपलब्ध साक्ष्य पेश करके अपने-अपने मामले को स्थापित करे और अदालत

को संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष को किसी विशेष गवाह या गवाहों से पूछताछ करने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है। फिर भी यदि कोई भी पक्ष किसी ऐसे साक्ष्य को रोकता है जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है और जो, यदि प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे साक्ष्य को रोकने वाले पक्ष के लिए प्रतिकूल है, तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (छ) के तहत एक अनुमान लगा सकता है। ऐसी स्थिति में विचार के लिए एक प्रश्न यह उठता है कि क्या न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को केवल दो पक्षों के बीच एक प्रतियोगिता में केवल एक अंपायर के रूप में बैठना चाहिए और लड़ाई के अंत में घोषित करना चाहिए कि कौन जीता है और कौन हारा है या पक्षकारों से स्वतंत्र, सत्य का पता लगाने और न्याय देने में कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाने का अपना कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है? यह एक अच्छी तरह से स्वीकार किया गया और स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को न्याय देने में कानून के अनुसार अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करना चाहिए, चाहे वह विवेकाधीन हो या अनिवार्य, क्योंकि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह न केवल न्याय करे बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि न्याय किया जा रहा है। न्यायालय को सच्चाई का पता लगाने और न्यायसंगत निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए संहिता की धारा 540 (नई संहिता की धारा 311) के हितकारी प्रावधानों को अधिनियमित किया गया है, जिसके तहत कोई भी न्यायालय जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है या उपस्थित किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है या फिर से पूछताछ कर सकता है, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है या पहले से ही जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है और फिर से जांच कर सकता है, जिससे विवाद में मामले पर प्रकाश डालने में सक्षम होने की उम्मीद की जाती है; क्योंकि यदि निर्णय तथ्यों की असंगत, अनिर्णायक और सट्टा प्रस्तुति पर दिए जाते हैं, तो न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे।"

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या धारा 540 न्यायालय को असाधारण शक्ति के प्रयोग में कोई अंतर्निहित सिद्धांत नहीं देती है और क्या उक्त धारा दिशाहीन, अनियंत्रित और अप्रचलित है। यद्यपि धारा 540 (नई संहिता की धारा 311), व्यापकतम संभव शर्तों में है और न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किए जाने के स्तर के संबंध में या उनके प्रयोग किए जाने के तरीके के संबंध में, किसी सीमा का आह्वान नहीं करती है, वह शक्ति उस सिद्धांत द्वारा सीमित है जो धारा 540 को रेखांकित करता है, अर्थात्, प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य को सभी विधिपूर्ण साधनों से सत्य को प्राप्त करके मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक न्यायालय को उपस्थित होना चाहिए। इसलिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा की सहायता का उपयोग केवल प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने या मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए ऐसे तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए और इसका उपयोग विवेकपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से क्योंकि शक्ति का कोई अनुचित या मनमौजी प्रयोग अवांछनीय परिणाम दे सकता है। इसके अलावा यह अनिवार्य है कि इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय द्वारा उचित सावधानी बरती जानी चाहिए और इसका उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा या बचाव पक्ष द्वारा या अभियुक्त के नुकसान के लिए छोड़ी गई कमी को भरने के लिए या अभियुक्त के बचाव के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने या प्रतिद्वंद्वी पक्ष को अनुचित लाभ देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और आगे अतिरिक्त साक्ष्य को पुनः विचारण के लिए या किसी भी पक्ष के खिलाफ मामले की प्रकृति को बदलने के लिए छद्म रूप में प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

"उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से जो विधि का सिद्धांत सामने आता है, वह यह है कि आपराधिक न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने या किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुलाने और फिर से जाँच करने की पर्याप्त शक्ति है, भले ही दोनों पक्षों के साक्ष्य बंद हों और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से स्थिति की अनिवार्यता द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, और निष्पक्षता और समझदारी ही एकमात्र

सुरक्षित मार्गदर्शक प्रतीत होती है और यह कि केवल न्याय की आवश्यकताएं किसी भी व्यक्ति की जाँच का आदेश देती हैं जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।"

(12) प्रतिवादी-अभियुक्त के विद्वान वकील को यह तर्क देने में पूरी तरह से उचित पाया गया कि याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता न केवल पहले दिन से ही बहुत ही अनौपचारिक दृष्टिकोण पर आगे बढ़ रहा था, बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की भी कोशिश कर रहा था, जिससे प्रतिवादी-अभियुक्त के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने का इरादा था। दलीलों के दौरान, जब याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से एक नुकीला सवाल पूछा गया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी को क्यों तलब किया गया और उनसे पूछताछ करने की मांग की गई, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और यह सही था क्योंकि यह रिकॉर्ड की बात थी। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता स्वयं निश्चित नहीं था कि धारा 311 C r P.C. के तहत उसके आवेदन को स्थानांतरित करने का उद्देश्य क्या था। इस प्रकार, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा धारा 311 Cr.P.C के तहत दायर आवेदन। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वास्तविक कारणों से आवेदन नहीं किया है। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को इसी कारण से भी बरकरार रखा जाना चाहिए।

(13) प्रतिवादी-अभियुक्त के विद्वान वकील को यह तर्क देने में पूरी तरह से उचित पाया गया कि याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता न केवल पहले दिन से ही बहुत ही अनौपचारिक दृष्टिकोण पर आगे बढ़ रहा था, बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की भी कोशिश कर रहा था, जिससे प्रतिवादी-अभियुक्त के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने का इरादा था। दलीलों के दौरान, जब याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से एक नुकीला सवाल पूछा गया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी को क्यों तलब किया गया और उनसे पूछताछ करने की मांग की गई, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और यह सही था क्योंकि यह रिकॉर्ड की बात थी। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता स्वयं निश्चित नहीं था कि धारा 311 C r P.C. के तहत उसके आवेदन को स्थानांतरित करने का उद्देश्य क्या था। इस प्रकार, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा धारा 311 Cr.P.C के तहत दायर आवेदन। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वास्तविक कारणों से आवेदन नहीं किया है। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को इसी कारण से भी बरकरार रखा जाना चाहिए।

(14) कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया।

(15) ऊपर उल्लिखित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान याचिका पूरी तरह से गलत धारणा है, योग्यता से रहित है और इसमें कोई सार नहीं है, इसलिए इसे विफल होना चाहिए। हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

(16) नतीजतन, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाता है, हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी

व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा